

MR. SPEAKER: All serious matters cannot be discussed in one day. We must find time for it...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I am raising a serious matter...

MR. SPEAKER: Mr. Kanwar Lal Gupta, this is an attempt to steal a march over others. I have already informed you that I am allowing a call-attention on that. You cannot raise it by a point of order. I am not allowing you any more. Do not record.

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, I want to make it clear on behalf of my Party and on behalf of the President of my Party, Mrs. Indira Gandhi, that the report which has appeared is absolutely baseless. Not a pie has been taken: I want to make it clear. I challenge, we are prepared for any inquiry. It is baseless.

MR. SPEAKER: I am allowing an opportunity for discussion (*Interruptions*) I have said that I am giving an opportunity for this. Nothing more.

SHRI NATHU SINGH (Dausa): There are CIA agents sitting in Indian Parliament. This is an insult to our country.

SHRI C M STEPHEN: You are the CIA: you have a man, Dr. Subramaniam Swamy.

MR. SPEAKER: I think you are quits now.

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Indira Gandhi Party took money from everybody.

श्रीधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : स्टीफन साहब के बयान के बाद इस बात पर एक बहस यहाँ पर होनी चाहिये **

MR. SPEAKER: Don't record.

Shri Hari Vishnu Kamath.

CHOWDHRY BALBIR SINGH: **

MR. SPEAKER: Nothing is recorded

Mr. Kamath.

12.25 hrs.

COMMITTEE ON PETITIONS

NINTH REPORT

श्री हरि बिष्णु कामत (होशियारबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से छठी लोकसभा की याचिका समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ ।

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND TWENTY-SECOND REPORT

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT (Dum Dum): I beg to present the hundred and twenty-second Report of the Public Accounts Committee on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fifteenth Report on Custom Receipts relating to Ministry of Finance.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

THIRTY-SECOND AND THIRTY-THIRD REPORTS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings:—

(1) Thirty-second Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Eighth Report of the Committee on Jute Corporation of India Limited—Government's Unfair Pricing Policy for Raw Jute.

(2) Thirty-third Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Third Report of the Committee on Jute Corporation of India Limited—Jute and Exploitation of Jute Growers.

12.27 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR THE ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT

श्री राम दिलास पातवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, विषय के विभिन्न भागों में राजनीतिक हत्या से भारत को वंचित होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र का जीवन विरोध पक्ष है। यदि विरोध पक्ष मर जाए तो लोकतंत्र स्वयं समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी तथा डा० राम मनोहर लोहिया ने अनुसार अच्छे साध्य के लिए उच्च माध्यम की आवश्यकता है। जहाँ सत्ता जनमत पर अव्यवस्थित कात् पाकर कायम की जाती है वहाँ लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाता। लोकतंत्र का आधार विरोध का आदर तथा जीवन के प्रति सम्मान है।

आज एशिया एवं अफ्रीका के अधिकांश देशों में हत्या की राजनीति तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। ईरान में शाह ने अपने विरोधियों को अधाधुंध मरवा डाला और अब इस्लामी गणतंत्र के दावेदार शाह का साथ देने वालों की हत्या करवा रहे हैं। आज भुट्टो की हत्या ने सारे विश्व को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। विगत 6 अप्रैल, 1979 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अपील के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी श्री सोलोमन महालंगू को फांसी दे दी। उनके अलावा और चार व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। इसके पूर्व भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी कि वे दक्षिण अफ्रीका के अग्रवैत नेता की जिन्दगी को बचाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें।

राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने भी दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों से अपील की थी कि वे सोलोमन महालंगू को फांसी पर ना लटकायें। समाचार के अनुसार पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में 132 व्यक्तियों को फांसी पर लटकामा गया था। इनमें एक स्वैत, 26 मिश्रित नस्ल तथा 105 अफ्रीकी थे।

इसके पहले नेपाल में दो नेपाली कांग्रेस के नेताओं को फांसी दी गई और इन सारी राजनीतिक हत्याओं का प्रभाव भारत के जनजीवन पर पड़ता है। नेपाली कांग्रेस, भुट्टो तथा दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक हत्या ने भारत के शान्तिप्रिय आत्मा को झकझोर दिया है और सब ओर से हत्या के विरोध में प्रदर्शनों एवं भावाच्च उठा रहे हैं। स्वयं भारत में भी कुछ वर्ष पहले यहाँ के प्रबल विरोध के बावजूद आंध्र के दो नक्सलवर्षी किसान नेताओं को फांसी दे दी गई।

अब पाकिस्तान और बंगलादेश के भीतर से भारत बंगलादेश एवं पाक एकीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। भारत सरकार को निश्चित रूप से भारत, पाकिस्तान एवं बंगलादेश के महासंघ की बात चलानी चाहिए।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि किसी देश के आंतरिक मामले के नाम पर अपनी आत्मा को नहीं बेचना चाहिए। यह चुप्पी भारत की सम्मतिता एवं संस्कृति के प्रतिफल है तथा इससे भारत सरकार की कमजोरी झलकती है। भारत सरकार को अपने देश से फांसी की सजा को समाप्त करना चाहिए तथा विश्व के किसी भी कोने में राजनीति हत्या की जाये तो बिना किसी भेद भाव के उसकी तीव्र भत्तना करनी चाहिए।

MR. SPEAKER: Prof. Mavalankar. Not here. Shri Rajagopal Naidu.

(ii) AMENITIES TO THE WORKERS OF THE STEEL YARD IN MANDI GOVIND GARH, PUNJAB

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Sir, the Steel Yard in Mandi Govind Garh, Punjab is managed by Punjab Small Scale Industries Corporation. It is the consignment agent of the Hindustan Steel Ltd. (SAIL). P.S.S.I.C. took contract from SAIL to load and unload the steel arriving at the Railway Station in Mandi Govind Garh and to give delivery of that steel to the steel rolling mills in that town. This Corporation is getting Rs. 26/- per tonne from the Steel Authority.

This Corporation instead of employing the workers directly engaged a middle-man contractor who is giving only Rs. 6/- per tonne to the workers not only that, he has not provided any facility to the workers as provided in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

As per that Act, canteens, Rest rooms, first aid facilities, wholesome drinking water, sufficient number of latrines and urinals have to be provided in that establishment. Nothing was arranged in the Steel Yard. Even the drinking water is not provided there.

When the representative of the workers represented to the Union